बिहार का चीनी उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। सारी अर्थ व्यवस्था इस उद्योग पर निर्भर है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह चीनी की समस्या को और चीनी मिलों की समस्या को सम्पूर्ण देश के नक्शे में रख कर देखें। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि एक ओर उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें बन्द हो जायेंगीं यह खतरा पैदा हो रहा है दूसरी ओर चीनी मिलों के नये लाइसैंस दिये जा रहे हैं। अगर चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के वास्ते नई मिलें खोलते हैं और उन में पूंजी लगाते हैं तो मेरी समझ में उस से कम पूंजी लगा कर जो मिलें आज चल रही हैं उन से चीनी के उत्पादन की कमी की पूर्ति की जा सकती है। मैं समझता हूं कि नई चीनी मिलों के लाइसैंस देना इस समय देश के हित में नहीं होगा। हमारे आंध्र और मद्रास के सदस्य मेरी बात का गलत अर्थ न लगायें। हम इस देश की अर्थ व्यवस्था को टुकड़ों में नहीं देख सकते हैं।

मैं यह भी मानता हूं कि इस चीनी के बारे में सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यक्षमता भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अब इस में न तो सरकार ने ही अपनी भूमिका ठीक तरह से अदा की है और न ही मिल मालिकों ने अदा की है। नई पूंजी लगा कर नई मिलें खोलने के बजाय आज जो चीनी मिलें पहले से चल रही हैं, उन में एफिशयेंसी लाई जाय और वहां पर गन्ने की किस्म सुधार सकें और उस से उत्पन्न होने वाली शर्करा की मात्रा में वृद्धि कर सकें व मिल मालिकों पर दबाय डाल सकें कि वह किसानों के लिए समुचित सिंचाई का प्रबन्ध करें तो चीनी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। हमारे महाराष्ट्र और आन्ध्र के परिश्रमी लोग अपनी पूंजी, अपना सरमाया कुछ उद्योग में लगा सकते हैं, मगर उत्तर और दक्षिण में इस संबंध में संघर्ष नहीं होना चाहिए और देश के सीमित साधनों का इस बारे में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। चीनी के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय हमें सभी स्वार्थों का, सभी हितों का समन्वय करना जरूरी है मैं जानता हूं कि यह काम सरल नहीं है। यह काम कठिनाइयों से भरा हुआ है। स्वार्थ आपस में टकराते हैं। और उन से रास्ता निकालना कठिन होता है। लेकिन एक संतुलित नीति का निर्धारण और दृढ़ता के साथ उस का कार्यान्वयन असम्भव नहीं होना चाहिए। मन्त्री महोदय क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं, प्रभाव रखते हैं और वह उत्पादकों, उपभोक्ताओं और इस उद्योग इन तीनों के हित में ऐसा योग बिठा सकते हैं जिस से कि इस चीनी उद्योग का विकास हो और साथ ही उत्पादकों के साथ और उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी न होने पाये।

मैं एक बात फिर कह दूं कि मैं ने उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की चर्चा की है। चूंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मुझे कठिनाइयों का पता है। आज यह उद्योग गहरे संकट में पड़ा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग संकट में पड़ गया तो वहां फिर जनता को काम देने के लिए और कोई उद्योग नहीं है। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं सरकार से इस बात का आग्रह करूंगा कि उसे इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रख कर अपनी नीति का निर्धारण करना होगा।

MR. CHAIRMAN : I have two announcements to make. One is that the 26th Report of the Business Advisory Committee would be presented now. The second is that this debate will go upto 6.30 P.M. and then it will be postponed for a day to be fixed.

Dr. Ram Subhag Singh.

18.15 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Twenty-Tixth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to present the twenty-sixth Report of the Business Advisory Committee.